DISH DOCTOR

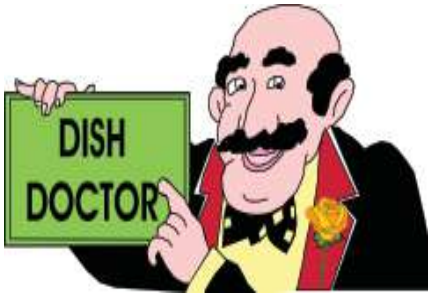

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

NEW FRAMEWORK

Q: The Department of Telecommunications has introduced a new Framework for Satellite Communication Network Authorisation along with guidelines for assigning spectrum to satellite communication network providers. What are the key highlights of this framework, and how will it benefit broadcasters, DTH operators, satellite communication companies and other users of satellite services in India?

Shyam Reddy, Satcom Consultant, Hyderabad

Ans.: The new framework marks a significant shift in India's satellite communications policy by replacing the earlier licensing regime with a simplified authorisation-based approach under the Telecommunications Act, 2023. It aims to create a transparent and technology-neutral environment for satellite communication services while simplifying approvals and encouraging greater investment.

The accompanying spectrum assignment guidelines provide clarity on how satellite spectrum will be allocated, enabling both existing operators and new entrants—including next-generation satellite broadband providers—to expand their services. For broadcasters, DTH operators, teleport providers and media companies, the framework promises improved regulatory certainty, easier access to satellite capacity and support for advanced applications such as UHD broadcasting, remote production, disaster recovery and live event contribution.

Overall, the reforms are expected to accelerate the growth of India's satellite ecosystem, promote innovation, improve digital connectivity in underserved areas and strengthen the country's position as a leading satellite communications market. As the detailed implementation guidelines evolve, stakeholders should closely monitor compliance requirements and emerging opportunities.■

नया फ्रेमवर्क

प्रश्नः दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑथराइजेशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदायकों को स्पेक्ट्रम देने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इस फ्रेमवर्क की मुख्य बातें क्या हैं और इससे भारत में प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों और सैटलाइट सेवाओं के अन्य यूजर्स को क्या फायदा होगा?

श्याम रेड्डी, सैटकॉम कंसल्टेंट, हैदराबाद

उत्तरः यह नया फ्रेमवर्क भारत की सैटेलाइट कम्युनिकेशन नीति में एक बड़ा बदलाव लाता है। यह दूरसंचार एक्ट, 2023 के तहत पुरानी लाइसेंसिंग व्यवस्था की जगह एक आसान, अथॉराइजेशन आधारित तरीका अपनाता है। इसका मकसद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए एक पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल माहौल बनाना है, साथ ही मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाना और ज्यादा निवेश को बढ़ावा देना है।

साथ में दी गयी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन गाइडलाइंस से यह साफ होता है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कैसे आवंटित किया जायेगा। इससे मौजूदा ऑपरेटरों और नयी कंपनियों-जिनमें अगली पीढ़ी के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रदाता भी शामिल हैं-को अपनी सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर, टेलीपोर्ट प्रदाता और मीडिया कंपनियों के लिए, यह ढ़ांचा बेहतर रेगुलेटरी स्पष्टता, सैटेलाइट क्षमता तक आसान पहुंच और यूएचडी प्रसारण, रिमोट प्रोडक्शन, डिजास्टर रिकवरी और लाइव इवेंट कंट्रीब्यूशन जैसे एडवांस्ड आवेदन के लिए सपोर्ट का वादा करता है।

कुल मिलकर इन सुधारों से भारत के सैटेलाइट इकोसिस्टम की ग्रोथ तेज होने, इनोवेशन को बढ़ावा मिलने, कम सुविधा वाले इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर होने और एक प्रमुख सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाजार के तौर पर देश की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार होंगी, संबंधित पक्षों को नियमों के पालन की जरूरतों और नये मौके पर बरीकी से नजर रखनी चाहिए।■